PUBLIC ADMINISTRATION (OPTIONAL) — PAPER II

UPSC Civil Services (Main) Examination, 2019

लोक प्रशासन (वैकल्पिक) — प्रश्न पत्र II

Time allowed: Three hours **Maximum marks: 250**

The questions of this paper in English and Hindi, grouped by marks (the printed paper numbers them Q1 to Q8; candidates answer five, with Q1 and Q5 compulsory). Read them with model answers and notes at swaadhigam.com/pyq/optional/public-administration/paper-2/2019.

10-MARK QUESTIONS

16 questions

1. The economic reforms have significantly infringed the basic values and spirit of the Indian Constitution. Examine. **10**

आर्थिक सुधारों ने भारत के संविधान के आधारभूत मूल्यों और आत्मा (भावना) का महत्त्वपूर्ण ढंग से अतिलंघन किया है। परीक्षण कीजिए।

2. Macaulay's ideas on Indian Civil Service corresponded to the elite theory of bureaucracy, which continue to persist. Do you agree? Justify. **10**

भारतीय सिविल सेवा पर मैकाले के विचार अधिकारीतंत्र की संभ्रांत थियोरी के समरूप हैं, जो अभी तक भी कायम हैं। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

3. Emerging developmental aspirations of the society necessitate the constitutional amendment to change the present safeguards available to the civil servants. Evaluate the pros and cons of such amendment. **10**

समाज की उभरती हुई विकासीय आकांक्षाएँ लोक सेवकों को उपलब्ध वर्तमान सुरक्षा साधनों में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन को आवश्यक बनाती हैं। ऐसे संशोधन के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का मूल्यांकन कीजिए।

4. In the text of Arthashastra, "the State is neither a police State nor merely a tax gathering State". Comment. **10**

अर्थशास्त्र के मूलपाठ में "राज्य न तो एक पुलिस राज्य है और न ही मात्र एक कर एकत्रित करने वाला राज्य"। टिप्पणी कीजिए।

5. Various commissions have reiterated the crucial role of the Governor in Indian system of governance, but the successive governments have not heeded to make the Governor's office apolitical. Examine with examples. **10**

विभिन्न आयोगों ने भारतीय शासन प्रणाली में राज्यपाल की निर्णायक भूमिका को बार-बार दोहराया है, किन्तु उत्तरोत्तर सरकारों ने राज्यपाल के पद को अराजनीतिक बनाने पर ध्यान नहीं दिया है। उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए।

6. There has been an opinion that the ethos of Indian Judicial System continue to be colonial. Suggest measures for raising the level of judicial excellence for achieving speedy justice. **10**

एक मत यह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था का विशिष्टाचार निरन्तर औपनिवेशिक बना हुआ है। त्वरित न्याय की प्राप्ति के लिए न्यायिक श्रेष्ठता के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उपाय सुझाइए।

7. All weather rural connectivity scheme to even unconnected rural habitations has the potential to transform the rural economy. Do you agree? Justify. **10**

सर्वमौसमी ग्रामीण संयोजकता योजना में असंयोजित ग्रामीण वासस्थानों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपान्तरण करने की क्षमता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

8. "The RTI has started its journey, but is far from its destination." In the view of the statement, examine the present status of the RTI movement. **10**

"सूचना के अधिकार ने अपनी यात्रा आरम्भ कर दी है, किन्तु यह अपनी मंजिल से बहुत दूर है।" इस कथन की दृष्टि से सूचना का अधिकार आन्दोलन की वर्तमान स्थिति का परीक्षण कीजिए।

9. The strategy to deal with the non-performing assets of banks may lead to overburdened taxpayers. Examine the role of government to protect the interests of both. **10**

हो सकता है कि बैंकों की गैर-निष्पादनी सम्पत्तियों से निपटने की रणनीति से करदाताओं पर अतिरिक्त भार पड़ जाय। इन दोनों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

10. Effective 'Performance Management System' needs to precede 'taking deadwood out' from bureaucracy. Comment. **10**

अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) में से 'अनुत्पादक लोगों को बाहर करने' के पहले प्रभावी 'निष्पादन प्रबन्धन प्रणाली' की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

11. The evidences suggest that the dream of deliberative democracy could not be realized in practice at the grassroot level. Evaluate the impediments in the functioning of Gram Sabha. **10**

साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि विचार-विमर्शी लोकतंत्र का सपना तृणमूल स्तर पर व्यवहार में अर्जित नहीं किया जा सका है। ग्राम सभा के प्रकार्यकरण में बाधाओं का मूल्यांकन कीजिए।

12. The concept of new localism arrangement may defeat the very purpose of local self-governance. Do you agree? Justify. **10**

नव स्थानीयतावाद व्यवस्था की संकल्पना स्थानीय स्वशासन के मूल उद्देश्य को ही परास्त कर सकती है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

13. The police-public interface is punctuated with distrust and fear. Suggest how the police can reform its image in the eyes of the public. **10**

पुलिस-जनता आमना-सामना (पारस्परिक सम्बन्धों) पर अविश्वास और डर के द्वारा विराम लग जाता है। सुझाइए कि जनता की नज़रों में पुलिस अपनी छवि को किस प्रकार सुधार सकती है।

14. 'Sevottam Scheme' had great potential to reform service delivery, but opportunity is frittered away. Comment. **10**

'सेवोत्तम योजना' की सेवा प्रदायगी में सुधार की अत्यधिक संभावना थी, परंतु अवसर को गँवा दिया गया है। टिप्पणी कीजिए।

15. Performance grants devolved by Finance Commission of India have increased the financial accountability of the local bodies. Elaborate. **10**

भारत के वित्त आयोग द्वारा अवक्रमित (डिवोल्ब्ड) निष्पादन अनुदानों ने स्थानीय निकायों की वित्तीय जवाबदेही में संबृद्धि कर दी है। विस्तार से समझाइए।

16. Accountability of regulatory bodies would address the problem of over-regulation and help make them truly facilitators. Analyze the present status of regulators and suggest measures to induce accountability in the mechanism. **10**

विनियामक निकायों की जवाबदेही, अति-विनियमन की समस्या को सुलझाने के साथ, उन्हें सच्चा सुकारक बनाने में सहायता करेगी। विनियामकों की वर्तमान प्रस्थिति का विश्लेषण करते हुए इस तंत्र में जवाबदेही उत्पन्न करने के उपाय सुझाइए।

20-MARK QUESTIONS

12 questions

17. Public Sector Undertakings were expected to take the Indian economy to the 'commanding heights', instead the successive governments have been pushing for disinvestment. Critically examine how the scenario has changed over the years. **20**

सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों से अपेक्षा की गई थी कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को 'प्रभावशाली ऊँचाइयों' तक ले जाएँगे, इसके बजाय क्रमिक सरकारें इनको विनिवेश की ओर धकेलती रही हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि विगत वर्षों में परिदृश्य कैसे-कैसे बदला है।

18. Article 356 acts "very much like the proverbial bolt from the blue ... without giving an opportunity or notice to the State Government to correct its alleged shortcomings". This phenomenon not only undermines the autonomy of the State Government, but also demeans the status of the President of India. Critically analyze. **20**

अनुच्छेद 356 राज्य सरकार को उसकी न्यूनताओं को सुधारने का अवसर या नोटिस दिए बिना ... बहुत हद तक आसमान से बिजली गिरने जैसा काम करता है। यह परिघटना न केवल राज्य सरकार की स्वायत्तता को क्षति पहुँचाती है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को भी कम करती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

19. Capacity issues relating to employees have hampered the implementation of several government programmes. Trace the reasons in the context of the provisions of the National Training Policy, 2012. **20**

कर्मचारियों से सम्बन्धित क्षमता मुद्दों ने अनेक सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को बाधित किया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के प्रावधानों के सन्दर्भ में, इसके कारणों का पता लगाइए।

20. Considerable attention has been paid to the restructuring of the administrative systems at the Central and local levels, but very few reforms have been undertaken at the State level. What steps would you suggest to rectify it? **20**

केन्द्रीय और स्थानीय स्तरों के प्रशासन तंत्र की पुनर्रचना के बारे में पर्याप्त ध्यान दिया गया है, किन्तु राज्य स्तर पर बहुत ही कम सुधार किए गए हैं। इस स्थिति को सही करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

21. "Strong PMO is anti-thesis to the feature of collective responsibility of Council of Ministers." Examine the issues in relation to the position of PMO vis-a-vis Council of Ministers in the light of this statement. **20**

"सशक्त प्रधानमंत्री कार्यालय (पी० एम० ओ०) मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व के लक्षण की विपरीतता है।" इस कथन के प्रकाश में पी० एम० ओ० बनाम मंत्रिपरिषद् की पद-स्थिति से सम्बन्धित मुद्दों का परीक्षण कीजिए।

22. It is observed that non-functioning of District Planning Committees is preventing the convergence of rural and urban planning needs. Do you agree? Justify. **20**

यह देखा जाता है कि जिला नियोजन समितियों की अकार्यशीलता ग्रामीण और नगरीय नियोजन की आवश्यकताओं की समानुरूपता को बाधित कर रही है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य बताइए।

23. The office of the District Collector has merely become a bureau for funnelling government schemes, collecting statistics and an officer on attendance for unending VIP duties. Critically examine its role in the light of the recommendations of the Second Administrative Reforms Commission. **20**

ज़िला कलेक्टर का कार्यालय केवल सरकारी योजनाओं को पहुँचाने, आँकड़ों का संकलन करने और एक ऐसा अधिकारी बनकर रह गया है जो कभी न समाप्त होने वाली वी० आइ० पी० ड्यूटी में तैनात रहता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आलोक में इसकी भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

24. Minimal accountability being the dominant norm in the political system, the Lokpal can only be an ideal institution with limited effectiveness. Explain. **20**

राजनीतिक तंत्र में न्यूनतम जवाबदेही के प्रभावी मानक होते हुए, लोकपाल केवल सीमित प्रभाविता वाली एक आदर्श संस्था ही हो सकती है। समझाइए।

25. Even though the law and order administration is a State subject, it is paradoxical that the Central agencies—NIA or paramilitary forces under the Union Government—have restricted the powers of State Governments. Discuss. **20**

यद्यपि कानून और व्यवस्था प्रशासन एक राज्य विषय है, तथापि यह विरोधाभासी है कि संघ सरकार के अधीन केन्द्रीय अभिकरणों—एन० आइ० ए० या अर्द्धसैनिक बलों—ने राज्य सरकारों की शक्तियों को सीमित कर दिया है। विवेचना कीजिए।

26. Efforts to strengthen State Finance Commissions have faced apathy of State Governments over the years, which has also affected the successive Central Finance Commissions in recommending appropriate fiscal transfers to local bodies. Substantiate the answer with examples. **20**

विगत वर्षों में राज्य वित्त आयोगों को सशक्त करने के प्रयासों को राज्य सरकारों की उदासीनता का सामना करना पड़ा है, जिसने क्रमिक केन्द्रीय वित्त आयोगों को भी स्थानीय निकायों को समुचित वित्तीय अंतरणों की सिफारिश करने में प्रभावित किया है। उत्तर को उदाहरणों सहित सिद्ध कीजिए।

27. 'NITI Aayog' has changed the way India strategized for economic development, but its effectiveness is yet to be seen, especially when its financial powers are far less than its predecessor. Analyze. **20**

भारत ने आर्थिक विकास के लिए जो रणनीति बनाई थी उसे 'नीति आयोग' ने बदल दिया है, किन्तु इसकी प्रभाविता को अभी देखा जाना शेष है, विशेष तौर से जब इसकी वित्तीय शक्तियाँ इसके पूर्ववर्ती की तुलना में बहुत कम हैं। विश्लेषण कीजिए।

28. The National Policy on Disaster Management envisages a paradigm shift from hitherto reactive post-disaster relief centric regime to more pro-active and enabling environment. Examine the responses of State Governments in this regard. **20**

आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय नीति में अब तक की प्रतिक्रियात्मक आपदा-पश्चात् राहत केन्द्रिक व्यवस्था के स्थान पर अधिक अग्रलक्षी और समर्थक वातावरण की ओर आगे बढ़ने की परिकल्पना की गई है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की अनुक्रियाओं का परीक्षण कीजिए।